1	2	3	4	5	6
17.	नागालैंड . .	1.026	01.026	2.301	6.201
18.	उड़ीसा . . .	5.105	5.110	15.960	27.000
19.	पंजाब . . .	2.134	2.134	8.519	8.519
20.	राजस्थान . .	2.397	2.388	15.519	15.519
21.	सिक्किम . .	1.026	0.513	2.151	1.538
22.	तमिलनाडु . .	11.030	11.000	26.810	26.810
23.	त्रिपुरा . .	2.050	1.026	4.852	4.327
24.	उत्तर प्रदेश . .	22.431	22.435	52.611	44.250
25.	पश्चिमी बंगाल . .	3.838	1.920	26.426	4.000
26.	अंडमान निकोबार .	—	—	0.100	4.075
27.	चण्डीगढ़ . .	—	—	0.100	—
28.	दादर और नागर हवेली .	—	—	0.100	0.100
29.	दमन और दियू . .	—	—	0.100	0.100
30.	दिल्ली . .	—	—	0.150	—
31.	लक्षद्वीप . . .	—	—	0.100	0.150
32.	पांडिचेरी . .	—	—	0.100	—
	योग	118.575	87.988	364.939	310.359

Malpractices of scientists of Indian Agricultural Institute

4044. SHRI M. A. BABY: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a report which appeared in the 'Indian Express' (New Delhi) dated the 27th October, 1991 regarding malpractices in evaluation by a top scientist of the Indian Agricultural Institute;

(b) whether an inquiry has been constituted by any internal or external agency and the findings thereof;

(c) whether any steps have been taken or are proposed to be taken with a view to prevent such malpractices and the details, thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI K. C. LENKA): (a) Yes, Sir.

(b) Inquiry revealed that there was no malpractice in evaluation.

(c) The process of evaluation involves checking, rechecking and re-evaluation by separate groups of scientists. Hence there is hardly any scope of anything going wrong in the final evaluation.

दिल्ली दुग्ध योजना को दूध की आपूर्ति

4045. डा० जिनेन्द्र कुमार जैन: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली दुग्ध योजना ने दूध के क्रय के लिए किसानों द्वारा गठित सहकारी समितियों को पंजीकृत किया है ;

(ख) यदि हां, तो विगत में यह पंजीकरण कब किया गया था ;

(ग) क्या यह सच है कि दूध की अधिक आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य से दिल्ली दुग्ध योजना ने दूध की आपूर्ति के लिए निजी क्षेत्र के एककों से भी संपर्क किया है ;

(घ) यदि हां, तो दिल्ली दुग्ध योजना को दूध की आपूर्ति करने के लिए सहकारी समितियों को प्रोत्साहित न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार भविष्य में दूध की खरीद केवल सहकारी समितियों से करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार रखती है; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०सी० लेंका) :(क) जी, नहीं ।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर पर ध्यान देते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं, अगस्त, 1991 के दौरान स्थानीय सहकारी समितियों ने संविदा अवधि के मध्य उच्च मूल्य की मांग करते हुए दिल्ली दुग्ध योजना को दूध की आपूर्ति बंद कर दी थी । इन स्थानीय सहकारी समितियों द्वारा उत्पन्न की गई स्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया था कि दिल्ली दुग्ध योजना के लिए ताज दूध की आवश्यकता के कुछ अंश की खरीद सहकारी क्षेत्र के अलावा अन्य स्रोतों से की जाए । तदनुसार, खुली निविदा आमंत्रित करके दिल्ली दुग्ध योजना को दूध की आपूर्ति करने के लिए गैर-सरकारी ठेकेदारों को आदेश दिए गए थे ।

(घ) और (ङ) दिल्ली दुग्ध योजना पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र के राज्य डेयरी सहकारी संघों तथा दिल्ली संघ शासित क्षेत्र की स्थानीय सहकारी समितियों तथा गैर सरकारी ठेकेदारों से दूध की खरीद कर रही है । दूध की खरीद में राज्य डेयरी सहकारी संघों को प्राथमिकता दी जाती है ।

Cost of production of foodgrains

4046. SHRI SURESH PACHOURI: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) what has been the cost of production of major foodgrains and cash crops during the last three years;

(b) what has been the growth rate in cost of production and procurement prices during the last three years; and

(c) the steps taken or proposed to be taken to minimise the cost of production and increase productivity?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN): (a) The cost of production of major foodgrains and cash crops during the latest available years is given in Statement-I. (*See* below).

(b) The growth rate (Percentage increase) in cost of production for the latest available years is given in Statement-II. (*See* below). The growth rate (percentage increase) in procurement prices is given in Statement-III. (*See* below).

(c) The Government is seized with the problem of rising cost of production and all possible measures are being taken to cut the cost as well as improve the productivity of crops through use of appropriate technology and transfer of these technologies to farmers by efficient delivery of inputs and service. It may be stated that a number of components in cost of production such as irrigation charges, power tariffs, agricultural credit and certain other inputs are subsidised in an effort of the Government to minimise the cost.